पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार में पुलिसिया कहर के बाद
अब गोरखपुर में आर० पी० एफ० रंगरूटों का तांडव

पूंजीवादी जनतंत्र के पगलाए हाथी का अब सिर्फ एक ही इलाज है--इसकी मौत !

चुनावी शोर-शराबे के ऐन बीच में विगत 9 एवं 10 सितम्बर को गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबन्धक की नाक के ठीक नीचे लेखा एवं ऑडिट विभाग के कर्मचारियों पर रेलवे सुरक्षा बल (आर० पी० एफ०) के रंगरूटों ने जिस बहशियाना ढंग से डण्डे बरसाये और हवाई फायर किये, इस पर अब किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। पुलिस, फौज और नौकरशाही ही तो इस जनतंत्र के असली खाने के दाँत हैं। बाकी, संसद विधान सभाएं और अन्य तथाकथित जनतांत्रिक संस्थाएं तो महज इसके दिखाने के दाँत हैं।

आर० पी० एफ० रंगरूटों के इस नंगनाच की वजह सिर्फ यह थी कि मुख्यालय परिसर में व्यवस्था कायम करने के नाम पर स्कूटरों-मोटर साइकिलों से हवा निकाल देने के मसले पर ऑडिट एवं लेखा विभाग के कुछेक लोगों से 9 सितम्बर को आर० पी० एफ के जवानों की झड़प हो गयी थी। इस झड़प के कुछ ही देर बाद बाहर एकत्र होकर खड़े रेल कर्मियों पर लाठियों-संगीने से लैस रंगरूटों की एक पलटन ने अपने एक कमाण्डेण्ट के निर्देश पर जमकर लाठियाँ बरसायीं।

इस अकारण लाठी चार्ज से गुस्साये रेलकर्मियों ने अगले दिन 10 सितम्बर को काम बन्द रखा और लाठीचार्ज के जिम्मेदार कमाण्डेण्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महाप्रबन्धक कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गये। लेकिन, धरना शुरू होते ही रंगरूटों की एक पलटन ने उसी कमाण्डेण्ट के इशारे पर एक बार फिर लाठी चार्ज करना शुरू किया। लेकिन, बगल में स्थित रेलवे प्रेस के मजदूरों ने अपने कर्मचारी साथियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए मोर्चा लेना शुरू किया तो शक्ति सन्तुलन गड़बड़ होता देख वे भाग खड़े हुए।

इस लाठीचार्ज से आक्रोशित कर्मचारियों को "समझाने बुझाने" के लिए महाप्रबन्धक अपने कक्ष से बाहर निकले ही थे कि रंगरूटों की एक बड़ी पलटन दुबारा लौटी। इस बार महाप्रबन्धक के सामने ही आर०पी०एफ० जवानों ने बाहर खड़े कर्मचारियों पर भी जमकर डण्डे बरसाये, लेखा कार्यालय में घुसकर कार्यरत कर्मचारियों पर भूखे भेड़ियों की तरह पिल पड़े, फर्नीचर को तोड़ डाला और ऐसी-ऐसी गालियों से नवाजा कि भठियारिनें भी पानी मांगें। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को आतंकित करने के लिए उन्होंने अन्धाधुन्ध हवाई फायरिंग भी की।

आर० पी० एफ० जवानों के इस नंगनाच में छः-सात कर्मचारी बुरी तरह घायल हुए। कुछ की हड्डियां टूटीं, कुछ लहूलुहान हो गये। लेकिन, रेल प्रशासन ने कर्मचारियों के आक्रोश पर पानी के छींट मारने के लिए घटना में शामिल दो जवानों को निलम्बित कर और विभागीय जांच बैठाकर कार्रवाई की खानापूरी कर ली, जो रेल प्रशासन के मूंसवों को भी एकदम साफ कर देता है।

दरअसल, रेल कर्मियों पर आतंक कायम कर रेल प्रशासन रेल विभाग में धीरे-धीरे लागू हो रही उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों और दिनों-दिन बढ़ती निरंकुशता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देना चाहता है। इस घटना के कुछ ही दिन पहले नियमितीकरण की मांग को लेकर रेलवे निर्माण विभाग के धरनारत कैजुअल श्रमिकों पर भी रेल प्रशासन ने आर० पी० एफ० से लाठियां चलवाकर जेल में ठूंस दिया था।

लेकिन, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उक्त घटना का कोई एकजुट विरोध न हो सका। यूनियनें, बयानबाजी कर चुप लगा गयीं। इसी तरह इस बार भी कर्मचारियों के आक्रोश को संगठित कर किसी लम्बे संघर्ष की तैयारी का रूप देना सम्भव नहीं लग रहा है। यूनियनें इतनी नपुंसक हो गयी हैं कि इस घटना के बाद भी वे 'औद्योगिक शान्ति' बहाल करने व सिर्फ आर० पी० एफ० के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कराने की खानापूरी के लिए ही चिन्तित हैं।

घटना के विरोध में लंच के समय इन यूनियनों ने एक-दो दिन आनुष्ठानिक सभाएं आयोजित कर अपनी लाज बचाने की कोशिश की। उधर, कर्मचारियों के गुस्से की आँच में अपनी चुनावी रोटियाँ सेंकने की लालच में चुनावी दलों के प्रत्याशियों के बीच भी सहानुभूति जताने की होड़ मच गयी है।

इन लाज बचाऊ सभाओं और रस्मी बयानबाजियों से अलग सिर्फ रेल के कारखानों के मजदूरों की एक दो साल पुरानी यूनियन 'इण्डियन रेलवे टेक्निकल एण्ड आर्टिजन इम्प्लाइज' एसोसियेशन' ने यांत्रिक कारखाना गेट पर सभा कर रेल प्रशासन की बढ़ती निरंकुशता के विरोध में एक लम्बे संघर्ष की रणनीति बनाने और सभी ट्रेडों एवं कैटगरी के मजदूरों-कर्मचारियों की व्यापक एकजुटता का आह्वान किया। इसके साथ ही, एक अन्य नवगठित मंच रेल मजदूर अधिकार मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी बैठकर जागरूक रेलकर्मियों से ट्रेड यूनियन धन्धेबाजों पर निर्भरता छोड़कर संघर्ष की कमान अपने हाथ में लेने का आह्वान किया।

लेकिन, फिलहाल ये आवाजें ठहराव व थकी-हारी दुनियादारी की मानसिकता में अनसुनी-सी बनकर रह जा रही हैं। भविष्य में यह चीज अगर आगे बढ़ती है तो बात आगे बढ़ सकती है। देर-सवेर होना यही है। हालात भी इसी ओर धकेल रहे हैं और एकमात्र रास्ता भी यही है।

सत्ता की निरंकुशता का शिकंजा पूरे समाज में कसता जा रहा है। रेल कर्मचारी, मजदूर, छात्र, महिलाएं कोई भी इस कहर से बचा हुआ नहीं है। पीलीभीत में आतंकवादियों के नाम पर एक स्वाभिमानी सिख को पुलिस थाने में ले जाकर टांगे चीर दी गयी, मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री की सभा में छात्राओं की बर्बर पिटाई हुई। हरिद्वार में भी छात्रा का यौन शोषण एवं उत्पीड़न करने वाले प्रवक्ता की गिरफ्तारी के लिए आन्दोलनरत छात्र-छात्राओं को घरों से बाहर निकालकर पीटा गया.....यह फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। कोई भी दिन खाली नहीं जाता जब देश के किसी हिस्से में जनता पर पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों की लाठियों-गोलियों का कहर बरपा न होता हो।

अब यह रूकने वाला नहीं। यह तो भविष्य के संकेत मात्र हैं। कारण यह है कि अपने संकटों से बदहवास पूंजीवादी जनतंत्र का हाथी पगला गया है। इससे बचने की अब सिर्फ एक सूरत बची है-इसकी मौत। यही अन्तिम विकल्प है। इस पर सोचने और अमल करने में बहुत देर करना जानलेवा ही साबित होगा।

• सुनील चौधरी